संसद के समक्ष अभिभाषण — 22 फरवरी 2010

लोक सभा	-	पंद्रहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत की राष्ट्रपति	-	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील
भारत के उपराष्ट्रपति	-	मोहम्मद हामिद अंसारी
भारत के प्रधानमंत्री	-	डॉ. मनमोहन सिंह
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्रीमती मीरा कुमार

माननीय सदस्यगण,

इस नए दशक में, संसद के दोनों सदनों के पहले सत्र के लिए आज आप जहां उपस्थित हुए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूं। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य, अपने देश को समृद्धि की ओर ले जाने और विश्व समुदाय में इसे उचित स्थान दिलाने के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे और इस दशक को गौरवशाली दशक बनाएंगे। आगे आपको बहुत अधिक विधायी कार्य करने हैं, इनके लिए आपका पूर्ण ध्यान अपेक्षित है।

मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं जिन्होंने हाल ही में पुणे में हुए आतंकवादी हमले में अपने प्रियजन खो दिए हैं। वामपंथी अतिवादियों की विवेकहीन हिंसा जारी है जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुए हाल ही के हमलों से स्पष्ट होता है, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस प्रकार के कायरतापूर्ण कार्य ऐसी हिंसा की चुनौतियों का और अधिक ताकत के साथ सामना करने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ करते हैं। मेरी सरकार ने वामपंथी अतिवादियों से हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत के लिए आने को कहा है। नागरिक प्रशासन को सुदृढ़ करने और सभी को सर्वांगीण विकास के लाभ पहुंचाने की हमारी योजना के पक्के इरादे के साथ जारी रहेगी।

मेरी सरकार को बहुलवाद और पंथनिरपेक्षता के मूल्यों को संरक्षित व मजबूत करने और सभी के लिए न्यायपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से तीव्र विकास सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट जनादेश मिला है। मई, 2009 में कार्यग्रहण करने के समय से ही मेरी

सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर अधिक तीव्र एवं सर्वांगीण विकास के वायदे को पूरा करने के लिए एकत्रित होकर कार्य किया है। हमारे इस वायदे का केन्द्र बिंदु आम आदमी था और है। वैश्विक महामंदी के बाद, अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट के दुष्प्रभावों और वर्ष 2009 के मध्य में देश के अधिकांश भागों में मानसून की विफलता से उपजे संकट, से आम आदमी को बचाना जरूरी था।

मेरी सरकार ने मौजूदा आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सजग एवं संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने संबंधी उपाय किए हैं। सरकार ने भिन्न-भिन्न राजनीतिक व क्षेत्रीय मांगों का समाधान ढूंढ़ने और अपनी संघीय व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में निष्ठा से कार्य किया है। विश्व समुदाय से संबंध बनाने की पहल में अपने सुविचारित राष्ट्रीय हितों को मजबूती से आगे बढ़ाया है। शासन की संस्थाओं एवं नागरिक समाज के बीच की भागीदारी में संवेदनशीलता लाई गई है।

अपनी अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहन देने की सुदृढ़ नीतियों के जरिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना किया गया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। आर्थिक विकास की दर, जो वर्ष 2008-09 में घटकर 6.7 प्रतिशत रह गई थी, वर्ष 2009-10 में बढ़कर करीब 7.5 प्रतिशत होने की संभावना है। जिस समय औद्योगिकृत देशों में विकास दर नकारात्मक रही, भारत की विकास दर प्रभावी गति से बढ़ती रही।

अप्रत्याशित और भयंकर सूखे के कारण वर्ष 2009 में अर्थव्यवस्था के प्रबंध में विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस गंभीर प्रतिकूल स्थिति के प्रभाव को न्यूनतम रखने में किसानों की मदद करने के लिए, मेरी सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कार्य किया। सूखा प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि से अब तक रुपये चार हजार करोड़ से भी अधिक की राशि आबंटित की जा चुकी है। डीजल सब्सिडी स्कीम शुरू की गई। सरकार ने कृषि संबंधी बुनियादी ढांचा सृजित करने के लिए, केन्द्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों, जैसे-'राष्ट्रीय कृषि विकास योजना' और 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन' की निधियों का इस्तेमाल करने की भी अनुमति दी है ताकि फसल विशेष के अनुसार कार्यनीति बनाई जा सके और सूखे के कारण कृषि उत्पादन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके। 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम' में संशोधन किया गया ताकि छोटे व सीमांत किसानों के खेतों में भी जल संरक्षण का कार्य किया जा सके। इन प्रयासों के कारण खाद्यान्न के उत्पादन की गिरावट को काफी हद तक रोका जा सका। रबी की पैदावार प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

हम अपनी खाद्य सुरक्षा को किसी भी प्रकार के संकट से मुक्त रखने में समर्थ रहे हैं, फिर भी खाद्यान्नों और खाद्य उत्पादों की कीमतों पर दबाव रहा है। घरेलू उत्पादन में कमी और विश्व स्तर पर चावल, दालों तथा खाद्य तेल के बढ़े हुए मूल्यों के कारण, कीमतों में बढ़ोतरी अपरिहार्य थी। यह मूल्य वृद्धि सर्वांगीण विकास की हमारी स्कीमों के कार्यान्वयन का भी कुछ हद तक प्रतिबिंबन है, जिनके तहत किसानों को खरीद कीमतों का अधिक भुगतान किया गया तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा अधिक खर्च किया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की आय में वृद्धि हुई।

बढ़ती खाद्य कीमतों से, आम आदमी को राहत देने के कार्य को मेरी सरकार लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। खाद्यान्नों की खरीद कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद, सार्वजनिक वितरण के प्रयोजन से केन्द्र द्वारा निर्धारित कीमतें वर्ष 2002 से अपरिवर्तित रखी गई हैं। अनिवार्य वस्तुओं के लिए आयात व्यवस्था को उदार बनाया गया है। सरकार ने अगले दो महीनों में खुले बाजार में तीस लाख टन गेहूं व चावल लाने और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ एवं राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ और उनकी संबद्ध सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 5 लाख टन गेहूं और 2 लाख टन चावल जारी करने का निर्णय किया है, ताकि खुदरा स्तर पर उपभोक्ता को राहत मिल सके। सरकार ने कार्डधारकों को जनवरी और फरवरी, 2010 के दौरान वितरित किए जाने के लिए छत्तीस लाख टन गेहूं व चावल की अतिरिक्त मात्रा जारी की है। यह मात्रा कार्डधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली सामान्य मात्रा के अतिरिक्त होगी। खाद्य तेलों और दालों पर सब्सिडी देने की स्कीम जारी रखी गई है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जमाखोरी रोककर और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में न आने वाले वाली खाद्य वस्तुओं की भारी मात्रा में खरीद करने के लिए राज्य एजेंसियों जैसे–नागरिक आपूर्ति निगमों का सही उपयोग करके राज्य स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करें। गेहूं और रिफाइंड चीनी के आयात को और उदार बना दिया गया है। चीनी की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। सरकार ने खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और समन्वित कार्यनीति बनाने के लिए हाल ही में राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा खाद्य व आपूर्ति मंत्रियों की बैठक आयोजित की। विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर विचार करने के लिए कोर ग्रुप गठित किया गया है जिसमें केन्द्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्री शामिल हैं।

हम अपनी खाद्य सुरक्षा को दीर्घ अवधि के लिए तभी सुनिश्चित कर पाएंगे जब हम कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करेंगे और साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार को नियंत्रित करने की नीतियों में भी व्यापक सुधार

करेंगे। मेरी सरकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के प्रति कृतसंकल्प है।

वर्ष 2010-11 के दौरान अपनी विकास-दर में और सुधार करने की दिशा में अब हम दृढ़ता से अग्रसर हो रहे हैं। मेरी सरकार वर्ष 2010-11 में 8 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का लक्ष्य रखेगी और वर्ष 2011-12 में 9 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का प्रयास करेगी। बुनियादी ढांचागत विकास, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम अधिक बल देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यह विकास प्रक्रिया समाज के कमजोर वर्गों के सरोकारों और कल्याण के प्रति पर्याप्त रूप से अनुकूल हो। हम ऐसा वातावरण तैयार करने की दिशा में कार्य करेंगे जिसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साथ सभी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन मिले।

मेरी सरकार ने देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए कई नए उपाय किए हैं ताकि आतंकवाद की भारी चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे समर्थ बनाया जा सके। राज्य व जिला पुलिस मशीनरी और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी को सक्रिय बनाना, किसी संभावित आतंकी हमले से तेजी व कारगर ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के चार केन्द्रों की स्थापना करना, आसूचना ब्यूरो के कर्मियों की संख्या बढ़ाना, आसूचना ब्यूरों में मल्टी एजेंसी सेंटर को सुदृढ़ करना ताकि वह चौबीसों घंटे कार्य कर सके और तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना इन उपायों में शामिल है।

आतंकवाद की सभी प्रकार की चुनौतियों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग रहती है। आतंकवादी गतिविधियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करना हमारी सैद्धांतिक नीति रही है। हमें लगातार निगरानी रखनी होगी और विश्वव्यापी आतंकी समूहों से निपटने के लिए नए-नए उपाय खोजने होंगे।

वर्ष 2009 के दौरान देश में आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ गई है। इसके बावजूद जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, यद्यपि वामपंथी अतिवाद विशेष चिंता का कारण बना हुआ है।

राष्ट्र को अपने सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है। हमारे ये सशस्त्र बल देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने और देश की सीमाओं की रक्षा करने में खरे उतरे हैं। सरकार सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अपने सशस्त्र बलों को अपेक्षित अस्त्र-शस्त्रों, उपकरणों एवं प्लेटफार्मों से

सुसज्जित करने के लिए हम आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। अग्नि-III मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमताओं का शानदार उदाहरण है और वे इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा के पात्र हैं। भारतीय सेना को मुख्य युद्धक टैंक, 'अर्जुन' सौंपने से प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के हमारे प्रयासों को नई ऊर्जा मिली है।

मेरी सरकार सैनिकों और पूर्व-सैनिकों के कल्याण के लिए दृढ़ संकल्प है। सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों एवं विवादों और अन्य अपीलों के निपटान के लिए 'सशस्त्र बल अधिकरण' का गठन किया गया है। अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के पेंशनरी लाभों में पर्याप्त सुधार करने के लिए सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि अब समय आ गया है जब हम यह सुनिश्चित करने पर जोर दें कि शासन प्रक्रियाएं संवेदनशील हों, प्रशासनिक साधन अधिक कारगर हों और कल्याण कार्यक्रमों का लाभ आम आदमी तक पहुंचे। सुशासन के सिद्धांतों के प्रति हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसी से सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की 'भारत निर्माण' और अन्य स्कीमों के तहत ग्रामीण एवं शहरी पुनर्निर्माण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' के कार्यान्वयन में गति आई है। वर्ष 2009-10 के दौरान, अब तक, 4.33 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 203 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए हैं। इस स्कीम से कमजोर वर्गों को लाभ मिला है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों की भागीदारी 52 प्रतिशत और महिलाओं की भागीदारी 49 प्रतिशत रही, जो उत्साहवर्धक है। इस स्कीम के परिणामस्वरूप ग्रामीण मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी हुई है।

मेरी सरकार भारत निर्माण के शेष कार्यों को दूसरे चरण में पूरा करने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्प है।

ग्रामीण आवास योजना घटक के अंतर्गत, वर्ष 2009-10 के दौरान, पिछले दिसम्बर तक 14 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है। ग्रामीण सड़क योजना घटक के अंतर्गत, नवंबर, 2009 तक 96 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण करके, लगभग 34 हजार गांवों को जोड़ा जा चुका है। ग्रामीण जल-आपूर्ति योजना घटक के अंतर्गत, वर्ष 2009-10 में 627 में से 586 ऐसी बस्तियों को जल की आपूर्ति कर दी गई है जिन्हें अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई थी। वर्ष 2009-10 में 1.79 लाख अपेक्षित गुणवत्ता-रहित बस्तियों में से लगभग 35 हजार

बस्तियों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सिंचाई योजना घटक के अंतर्गत, जिसकी शुरुआत वर्ष 2005-06 में की गई थी, वर्ष 2011-12 तक एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 31.12.2009 तक 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' के फलस्वरूप 67 हजार से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 84 लाख परिवारों को बिजली के मुफ्त कनेक्शन दिए गए हैं। वर्ष 2014 तक 40 प्रतिशत ग्रामीण टेली-डेनसिटी प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ किए गए हैं।

हमारे देश के शहरी क्षेत्र जहां एक ओर चुनौती खड़ी करते हैं वहीं अनेक अवसर भी प्रदान करते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने तथा अवसरों का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2005 में 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन' प्रारंभ किया गया। इस मिशन के अंतर्गत, शहरी विकास और शहरी गरीबों के कल्याण के लिए रुपये एक लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

हमें शहरी आवास और स्लम क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होगा। सरकार महत्वाकांक्षी 'राजीव आवास योजना' पर कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य ऐसे राज्यों की सहायता करना है जो स्लम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का अधिकार देने के इच्छुक हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्लम निवासियों के लिए हमारे शहरों के भीतर ही निश्चित स्थान निर्धारित करना होगा और इन शहरों को स्लम रहित बनाने के लिए वांछित परिवर्तन करने और इनका पुनर्विकास करने का प्रयास किया जाएगा।

सतत एवं सर्वांगीण विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का बहुत महत्व है। सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र पर गठित कार्यबल की सिफारिशें शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। ऋण प्राप्ति सुविधा में सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास, जिला उद्योग केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, कच्चे माल की आपूर्ति में सुधार, उत्पाद विपणन की सुगमता और संस्थागत सुधार इनमें शामिल हैं।

मेरी सरकार सीमावर्ती राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय विकास के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की पक्षधर है।

प्रधानमंत्री की जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस पहल के अंतर्गत सड़कों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

और आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का कार्य तत्काल आधार पर शुरू किया गया है। सर्दी के महीनों में राज्य को 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्रदान की गई।

मेरी सरकार, उत्तर-पूर्व राज्यों में बुनियादी ढांचे के तीव्र विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों की राजधानियों और इन राज्यों में प्रत्येक जिले को दो लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 1600 किलोमीटर से अधिक लंबे अरूणाचल राजमार्ग का निर्माण शामिल है। अरूणाचल प्रदेश के सभी सीमावर्ती गांवों को 'होम लाइटिंग सिस्टम' मुहैया कराने के लिए विशेष कार्यक्रम का काफी हद तक कार्यान्वयन हो चुका है।

हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्गों को भी सफलता की इस कहानी का हिस्सेदार बनाया जाए।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अंतर्गत, अभी तक लगभग 7 लाख अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। शेष दावों का यथाशीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे।

सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए व्यापक रोडमैप तैयार किया है। वर्ष 2008-09 में अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए ऋणों में ₹ 82 हजार करोड़ तक वृद्धि हुई, जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण के 12 प्रतिशत से अधिक है। केन्द्र सरकार में रिक्त पदों पर अल्पसंख्यकों की भर्ती में बढ़ोतरी हुई है और नई भर्तियों में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो वर्ष 2006-07 में 7 प्रतिशत था, बढ़कर वह 2008-09 में 9 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

अल्पसंख्यक बहुल जिलों में बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत बहुत अच्छी रही है। वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई तीन छात्रवृत्ति स्कीमों को जोरदार समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़कर लगभग 15 लाख तक पहुंच गई है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में बालिकाओं की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

मेरी सरकार संसद के इस सत्र के दौरान वक्फ अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव पेश करेगी।

हमारी एकता और सामाजिक सौहार्द ही, आतंकवादियों और उनकी विघटनकारी योजनाओं का सही जवाब है। इसीलिए हमारी सरकार अपने सामाजिक ताने-बाने की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसी प्रयोजन से, हम संसद के इस सत्र के दौरान 'सांप्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण एव पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005' को शीघ्र पारित करवाने का प्रयास करेंगे।

मेरी सरकार मई, 2008 में राज्य सभा में पेश किए गए महिला आरक्षण विधेयक को शीघ्र पारित करवाने के लिए वचनबद्ध है। माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि आप सब इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव की ओर विशेष ध्यान दें।

पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के उद्देश्य से, संविधान में संशोधन करने के लिए दो विधेयक पहले ही पेश किए जा चुके हैं। आशा है कि इस सत्र में इन्हें पारित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय युवा कोर स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत 25 से 35 वर्ष के युवा वर्ग को राष्ट्र निर्माण संबंधी कार्यों में दो वर्ष तक सेवा करने योग्य बनाया जाएगा। पहले चरण में बीस हजार स्वयंसेवकों को लगाया जाएगा और जम्मू-कश्मीर में डल झील की सफाई करने जैसे विभिन्न रचनात्मक सामाजिक कार्यों में उनकी सेवाएं ली जाएंगी।

सभी क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करना आवश्यकता है। सरकार ने 'सर्व शिक्षा अभियान' एवं 'मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में भारी निवेश किया है और नए 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा का सार्वजनीकरण करने की दिशा में प्रयास कर रही है। 'बच्चों का नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' अधिसूचित किया जा चुका है जो पहली अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगा। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों में 373 आदर्श महाविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक स्कीम अनुमोदित कर दी गई है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' की स्थापना की गई है जिससे देश के लगभग 18 हजार महाविद्यालयों और 400 विश्वविद्यालयों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों द्वारा लिए जाने वाले शैक्षिक ऋणों के ब्याज पर सब्सिडी देने की भी स्कीम शुरू की गई है। 'साक्षर भारत' नाम से एक नया अभियान चलाया गया है जिसमें महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

मेरी सरकार शैक्षिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह शैक्षिक ढांचा विस्तार, समावेशन और उत्कृष्टता के तीन स्तंभों पर आधारित होगा। भारत में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान की नियामक संस्था के रूप में 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद' की शीघ्र स्थापना की जाएगी जिसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। सरकार एक ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविख्यात और उत्कृष्ट अकादमिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके और व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के लिए विदेशों से शिक्षा प्रदाताओं को लाया जा सके।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास में कम से कम 10 प्रतिशत इक्विटी के पब्लिक ऑफर के जरिए आम आदमी को भागीदारी का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने लाभकारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 'राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। 'जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन' शुरू किया गया जिसके अंतर्गत वर्ष 2022 तक 20 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

'ऊर्जा दक्षता वृद्धि मिशन' का अनुमोदन किया जा चुका है और जिसके अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के अंत तक 10 हजार मेगावाट बिजली की बचत होने की आशा है।

पर्यावरण संरक्षण एवं वन संरक्षण से संबंधित सिविल मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटान सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009' (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बिल, 2009) पेश किया गया है।

हमारी अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह तेल और गैस पर आश्रित है। लगभग एक दशक तक उत्पादन में गतिरोध बने रहने के बाद, वर्ष 2009-10 में 20 नए तेल क्षेत्रों की खोज होने से तेल उत्पादन क्षमता में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

मेरी सरकार, गैस और पेट्रोलियम उत्पादों को आम आदमी तक अधिक से अधिक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। 'राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक योजना' नाम से गांवों में एलपीजी वितरण की एक नई योजना आरंभ की गई है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार वर्ष 2012 तक 'घर-घर बिजली' पहुंचाने के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के विशेष प्रयास किए गए हैं। फलस्वरूप, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दसवीं योजना में शामिल क्षमता से तीन गुना अधिक क्षमता वृद्धि की संभावना है।

मेरी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों को तीव्र गति से करने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 20 किलोमीटर के निर्माण कार्य का लक्ष्य रखा है। कई नीतिगत पहलें की गई हैं ताकि एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास कार्य में नई गति आई है।

नागर विमानन क्षेत्र भी इस विश्व मंदी से अप्रभावित नहीं रह सका। विशेषकर हमारी राष्ट्रीय विमान सेवा, 'एयर इंडिया' तो बुरी तरह प्रभावित हुई। मंत्री समूह के सजग मार्गदर्शन में इसके यथाशीघ्र पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं।

विमानपत्तनों, विशेषकर चार महानगरीय विमानपत्तनों का विस्तार एवं आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है। दिल्ली विमानपत्तन परियोजना जुलाई, 2010 तक अर्थात् राष्ट्र-मंडल खेलों से काफी पहले ही पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। विमानपत्तन के क्षेत्र में नियामक कार्यों के निष्पादन के लिए 'विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण' की स्थापना की गई है।

मेरी सरकार, 'राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम' चला रही है जिसके अंतर्गत पत्तन और जहाजरानी क्षेत्र में चिह्नित परियोजनाओं पर निजी निवेश सहित एक लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश होगा। 'भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय' ने पूरी तरह से कार्य करना आरंभ कर दिया है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, विशाखापट्टनम और कोच्चि में इसके कैंपस खोले गए हैं।

भारतीय रेल इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरोती है। मेरी सरकार रेलवे की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और रेल प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा में सुधार करने के साथ-साथ यात्री गाड़ियों और मालगाड़ियों की गति में वृद्धि करने के प्रति वचनबद्ध है।

संपूर्ण कश्मीर घाटी में 'काजीगुंड से बारामूला' तक रेल सेवाएं शुरू हो चुकी हैं जिससे हमारे देश के सभी क्षेत्रों के विकास के प्रति मेरी सरकार की वचनबद्धता प्रदर्शित होती है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की 9 मुख्य राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित वित्त-पोषण की व्यवस्था करने के उद्देश्य से एक विशेष 'उत्तर-पूर्व रेल विकास निधि' का सृजन किया गया है।

भारतीय रेलवे ने पूर्वी और पश्चिमी मुख्य मार्गों पर महत्वाकांक्षी 'डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर' भी शुरू किया है। इस परियोजना से भारत के विकास को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।

हमारी सरकार ने जापान सरकार के साथ साझेदारी में एक महत्वाकांक्षी परियोजना 'दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर' के क्रियान्वयन में प्रगति की है। यह चुनौतीपूर्ण पहल पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल गुणवत्तायुक्त बुनियादी ढांचा, कारगर परिवहन,

विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति तथा प्रभावी लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराकर छह राज्यों में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करेगी।

मेरी सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक संचार सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के प्रति कटिबद्ध है। ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने हेतु 'विश्व सेवा दायित्व निधि' से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने देश भर के दूरस्थ स्थानों को जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में 10 हजार टावर स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। वर्ष 2012 तक 60 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन के लक्ष्य में से अब तक 57 करोड़ से भी अधिक कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इनमें से अकेले दिसम्बर, 2009 में ही लगभग दो करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं, जो अभूतपूर्व वृद्धि कही जा सकती है।

'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' के तत्वावधान में 'मिशन निर्मल गंगा' यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2020 तक किसी भी शहरी नाले और औद्योगिक बहिस्राव को शोधन किए बिना गंगा में नहीं बहने दिया जाएगा। गंगा की 'निर्मल धारा' और 'अविरल धारा' को सुनिश्चित करने के इस कार्य में केन्द्र और संबंधित राज्यों के संगठित और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता होगी।

हम जिस समावेशी समाज की आकांक्षा करते हैं, उसमें निष्पक्ष न्याय प्रणाली तक जनता की पहुंच और भरोसा होना आवश्यक है। सरकार ने 'राष्ट्रीय न्याय एवं विधि सुधार मिशन' बनाने का निर्णय लिया है जिसका उद्देश्य सरकार को एक जिम्मेदार एवं सजग पक्षकार बनाना, न्यायिक प्रबंधन की शुरुआत करना, न्यायालय प्रशासन और केस प्रबंधन में सुधार करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को अपनाना तथा लंबित मुकदमों की संख्या को कम करना है।

'सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य' अभी भी हमारे लिए एक राष्ट्रीय चुनौती बना हुआ है। 'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के जरिए जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को क्रियाशील किया गया है। इसके लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें कम चिकित्सा सुविधा वाले क्षेत्रों में मेडिकल, नर्सिंग और पराचिकित्सा संस्थानों की स्थापना, विशेषज्ञों और सुपर-विशेषज्ञों के लिए अतिरिक्त सीटों का सृजन और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करने के लिए चिकित्सकों को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रारंभिक आंकड़े, इस मिशन के सकारात्मक प्रभाव को इंगित करते हैं।

मेरी सरकार ने इन्फ्लूएंजा एच1एन1 नामक विश्वव्यापी महामारी से निपटने के लिए तत्परता से कार्य किया। देश में आने वाले एक करोड़ से भी अधिक यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जांच की गई। एच1एन1 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाएं स्थापित की गईं, राज्यों को औषधियों की दो करोड़ खुराक निःशुल्क

वितरित की गई और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 15 लाख टीकों का आयात किया गया। देश में पहली बार इन्फ्लूएंजा एच1एन1 का टीका विकसित किया जा रहा है, जो इस वर्ष उपलब्ध हो जाएगा।

मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 'आयकर अधिनियम, 1961' में संशोधन करना शामिल है जिससे केंद्र सरकार गैर-संप्रभुता वाले क्षेत्रों के साथ कर संबंधी समझौते कर सके। बड़े क्षेत्रों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के लिए करार करने के उद्देश्य से वार्ता शुरू करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। स्विट्जरलैंड के साथ कर-संधि के लिए पुनर्वार्ता चल रही है। भारत कर संबंधी सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने तथा कर चोरी की सुविधा देने वाले क्षेत्रों के खिलाफ कार्रवाई करने से संबंधित वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है।

समाचार और मनोरंजन के साधन सभी के लिए वहनीय तथा सर्वसुलभ होने चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हैड एंड इन द स्काई सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु दिशा-निर्देश अधिसूचित करने के अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के डिजिटलीकरण पर विचार किया जा रहा है। पहली बार दूरदर्शन राष्ट्रमंडल खेल-2010 का 'हाई डेफीनिशन फॉर्मेट' के साथ प्रसारण करेगा। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय फिल्मों तथा संगीत रचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और हमारे कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है।

भारत के सभी नागरिकों को बायोमीट्रिक प्रणाली के आधार पर विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए 'भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण' स्थापित किया गया है। सरकार के प्रमुख कल्याण कार्यक्रमों और जनसेवाओं के लक्ष्यों एवं डिलीवरी को खासकर गरीबों तथा अलग-थलग पड़े लोगों तक पहुंचाने में यह बृहत् एवं अभूतपूर्व कार्यक्रम कारगर सिद्ध होगा। विशिष्ट पहचान संख्याओं का पहला सेट वर्ष 2011 के पूर्वार्द्ध में जारी होने की संभावना है।

कुछ चुने हुए अग्रणी कार्यक्रमों और अन्य कार्यों की समीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में एक 'डिलीवरी मॉनीटरिंग यूनिट' (डीएमयू) की स्थापना की गई है। इस यूनिट की प्रगति से राष्ट्र को अवगत कराने के लिए संबंधित नोडल मंत्रालयों ने अपनी-अपनी वेबसाइटों पर तिमाही डीएमयू रिपोर्टें प्रदर्शित करनी शुरू कर दी हैं।

सरकार, अपने लिए और उद्योग, उद्यमियों, प्रौद्योगिकीविदों और शिक्षाविदों के लिए एक नवाचार कार्यनीति बनाने के लिए वचनबद्ध है जिसमें विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में नए बदलाव लाने के लिए आवश्यक सर्वांगीण विकास और उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

देश अक्तूबर, 2010 में 19वें प्रतिष्ठित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इस आयोजन की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। खेलों का सुचारू और सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा।

हमने वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाई है और अपने देश तथा देश के बाहर के क्षेत्रों में शांति, स्थायित्व और प्रगति के लिए भी कार्य किया है। सरकार, विश्व के साथ हमारे राष्ट्र निर्माताओं द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित अपनी सक्रिय सहभागिता निभाती रहेगी और इसका उद्देश्य परस्पर निर्भर विश्व में त्वरित एवं सर्वांगीण आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन के हमारे लक्ष्यों को आगे बढ़ाना होगा।

भूटान के राजा एवं प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, मालदीव के राष्ट्रपति और नेपाल के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भारत यात्राओं ने पड़ोसी देशों के साथ हमारी मित्रता और पारंपरिक संबंधों को नए आयाम दिए हैं। श्रीलंका में हुए चुनावों के बाद, अपनी साझेदारी को बढ़ाने के लिए हम वहां की सरकार के साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे। भारत, संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में तमिल अल्पसंख्यकों के लिए माननीय एवं पुनर्वास प्रयासों तथा दीर्घकालिक पुनर्निर्माण कार्यों में योगदान करेगा। अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत ने सहयोग के कई महत्वपूर्ण सोपान तय किए हैं और हम अफगानिस्तान के विकास प्रयासों में उनके साथ साझेदारी करते रहेंगे। यदि पाकिस्तान आतंकवाद के खतरे को गंभीरता से ले और भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए तो भारत, पाकिस्तान के साथ भी सार्थक संबंध तलाशने के लिए तैयार है।

बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा ने भारत-अमेरिकी साझेदारी के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर और आगे विस्तार की नींव तैयार कर दी है। मेरी और प्रधानमंत्री की रूस यात्राओं ने समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मित्रता को फिर से ताजा किया है तथा सहयोग के नए द्वार खोले हैं। नई दिल्ली में हुई दसवीं भारत-यूरोपीय संघ शिखर वार्ता यूरोप के साथ विस्तार पाती हमारी साझेदारी के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। चीन के साथ हमारी नीतिगत और सहकारी साझेदारी उत्तरोत्तर, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। जापान के प्रधानमंत्री की यात्रा ने सभी क्षेत्रों में हमारे सहयोग की गति को तीव्रतर बनाने की हमारी पारस्परिक इच्छा को प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री ने 'ब्रिक' देशों की पहली शिखर वार्ता में भाग लिया।

मेरी सरकार ने 'लुक ईस्ट' नीति का पूरे उत्साह के साथ अनुसरण किया है। कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति हमारे गणतंत्र दिवस समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि थे। सरकार ने मंगोलिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया एवं मलेशिया के प्रधानमंत्रियों की मेजबानी की। भारत-आसियान मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर तथा भारत-आसियान ढांचे एवं पूर्व एशिया शिखर वार्ता प्रक्रिया के भीतर कई नई पहलों की शुरुआत, हमारे देश को एशिया-प्रशांत क्षेत्रों से जोड़ेगी।

तज़ाकिस्तान की मेरी यात्रा तथा शंघाई सहयोग संगठन की शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की पहली बार उपस्थिति, मध्य एशिया के साथ मित्रता और आपसी समझ के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने की सरकार की नीति को दर्शाती है। तुर्की के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से तुर्की के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं।

मिस्र में गुटनिरपेक्ष शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री की शिरकत ने विकासशील देशों के साथ हमारे संबंधों को और सुदृढ़ किया है। खाड़ी और पश्चिम एशिया के देशों पर हम विशेष ध्यान देते रहेंगे। फिलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी हितों के लिए भारत ने अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है। नामीबिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा और हमारे उपराष्ट्रपति की बोत्स्वाना, मालावी और जांबिया की यात्रा से अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हमारे संबंध और गहरे हुए हैं। हम लैटिन अमेरिका के साथ लगातार बढ़ते सहयोग को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।

आतंकवाद, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं आर्थिक संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के संबंध में भारत का दृष्टिकोण उपयुक्त मंचों पर स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाता रहा है। वैश्विक शासन की संस्थाओं में सुधार का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा में शीर्ष पर रखा गया। ग्रुप-20 प्रक्रिया, ग्रुप-8 एवं ग्रुप-5 शिखर वार्ता और कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत की आवाज पूरे सम्मान के साथ सुनी गई।

हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि प्रवासी भारतीय समुदाय ने विश्व स्तर पर जीवन के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं और इसके लिए उन्हें पर्याप्त सम्मान भी प्राप्त हुआ है। 'प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय वैश्विक सलाहकार परिषद' की पहली बैठक इस वर्ष हुई। अगले नियमित आम चुनावों के समय तक सरकार विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को मतदान के अवसर प्रदान करने के लिए कार्य करेगी। भारतवंशियों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति हम वचनबद्ध हैं। इस उद्देश्य से 'भारतीय समुदाय कल्याण निधि' स्थापित की गई है।

देश के नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के महत्वाकांक्षी विस्तार के एक घटक के रूप में अतिरिक्त 'दाबानुकूलित भारी जल रिऐक्टरों' के निर्माण और 'हल्के जल रिएक्टर'

स्थापित करने के लिए स्थलों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सिविल नाभिकीय सहयोग के शुरू हो जाने के फलस्वरूप आयातित ईंधन उपलब्ध हो जाने से, 'राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना' की दो इकाइयों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है और आशा है कि एक और इकाई शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी। सिविल नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए रूस, मंगोलिया, नामीबिया, अर्जेंटीना और युनाइटेड किंगडम के साथ नए करार किए गए हैं और कुछ अन्य करारों पर बातचीत चल रही है।

टेली-चिकित्सा, टेली-शिक्षा के क्षेत्रों और ग्राम संसाधन केंद्रों में अंतरिक्ष कार्यक्रम राष्ट्र को लगातार सामाजिक सेवाएं मुहैया करा रहा है। पोलर सेटेलाइट प्रक्षेपण यान से ओसियनसैट-2 उपग्रह सफलतापूर्वक छोड़ा गया। निकट भविष्य में स्वदेशी क्रायोजेनिक युक्त जीएसएलवी-डी3 प्रक्षेपण यान का उड़ान परीक्षण तथा कार्टोसैट-2बी, इनसैट-3डी और रिसोर्ससैट-2 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना है। जीएसएलवी-मार्क III प्रक्षेपण यान को और विकसित किया जाएगा तथा चन्द्रयान-2 मिशन से संबंधित कार्य प्रारंभ किए जाएंगे।

हमारा देश एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। हमारे राष्ट्रनिर्माताओं ने राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का जो सपना संजोया था, उसे साकार करने के हम इतने करीब कभी नहीं थे जितने आज हैं। इन आकांक्षाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त, 1947 की मध्य-रात्रि को इसी हॉल में इन शब्दों में कहा था:

> "भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों लोगों की सेवा, जो पीड़ित हैं। इसका अर्थ है गरीबी और अज्ञान तथा रोग और अवसर की असमानता को समाप्त करना।"

हमने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, राह लंबी है किंतु हमारी यात्रा जारी है। तो आइए, पूरे विश्वास के साथ एक नए एवं उज्जवल भविष्य की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें।

जय हिन्द।